मुख्यमंत्री भजनलाल ने लोकदेवता बाबा रामदेव मंदिर के दर्शन किये

उन्होंने एक किलोमीटर पैदल यात्रा के बाद मैगा आई स्क्रीनिंग कैंप का उद्घाटन किया

जैसलमेर/पोकरण, 31 जुलाई (नि.सं.)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गुरुवार को बाबा रामदेव की नगरी रामदेवरा पहुंचे। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले बाबा रामदेव पैनोरमा का दौरा किया। इसके बाद, वे पैनोरमा से रामदेवरा मंदिर तक पैदल चल कर बाबा रामदेव के दर्शन करने पहुंचे। इस दौरान सीएम ने मेगा आई स्क्रीनिंग कैंप का उद्घाटन किया।

- **सक्षम संस्था द्वारा लगाया जा रहा नेत्र कुंभ 33 दिन चलेगा। इसमें मरीजों को चश्मा, दवाई तथा इलाज निशुल्क किया जायेगा।**

भजनलाल शर्मा हाथ में ध्वजा लिए पैनोरमा से करीब एक किलोमीटर की पैदल यात्रा करके बाबा रामदेव के समाधि परिसर पहुंचे। यहां उन्होंने लगभग 20 मिनट तक पूजा-अर्चना की।

उन्होंने कहा कि लोक देवता बाबा रामदेव की पुण्यभूमि पर पहली बार ऐतिहासिक नेत्र-कुंभ का आयोजन हो रहा है। मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे यहां आने का अवसर प्राप्त हुआ।

उन्होंने कहा, पोकरण, जैसलमेर, बाड़मेर और फलोदी की पहचान विश्व स्तर पर पर्यटन के क्षेत्र में रही है। बाबा रामदेव ने इस पावन भूमि पर जन्म लेकर सामाजिक समरसता की स्थापना की थी। इस नेत्र-कुंभ में, मेले में आने वाले लगभग सवा लाख लोगों की निशुल्क नेत्र जाँच की जाएगी। ये कैंप सक्षम संस्था की ओर से लगाया जा रहा है। सक्षम संस्था के राष्ट्रीय संगठन मंत्री चंद्रशेखर ने बताया कि रुचिचा धाम में 33 दिनों तक चलने वाले इस नेत्र-कुंभ में मरीजों की आंखों की जांच की जाएगी।

रुणिचा धाम परिसर में लगभग 1 एकड़ भूमि पर अस्थायी अस्पताल तैयार किया गया है। यहां आधुनिक चिकित्सा उपकरणों और विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम मौजूद रहेगी। कमजोर नज़र वाले लोगों को चश्मा दिया जाएगा। फ्री दवाइयां दी जायेंगी, तथा गंभीर मरीजों का कैंप में ही इलाज भी होगा।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को रामदेवरा में लोकदेवता बाबा रामदेव के दर्शन किये। उन्होंने हाथ में ध्वजा लेकर पैनोरमा से बाबा रामदेव के समाधि परिसर तक पैदल यात्रा की।

महेश जोशी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

साक्ष्य नहीं है और परिवादी यह राशि कहां से लाया, उसका भी उल्लेख नहीं है। इसके अलावा, ईडी अपनी रिपोर्ट में जोशी के बेटे की फर्म में 50 लाख रुपए का लेनदेन बता रही है। यह राशि बेटे की कंपनी ने लोन के तौर पर ली थी और उसे लौटाया भी जा चुका है। वहीं, इस राशि को लेकर सिविल केस भी लंबित चल रहा है।

ईडी कोर्ट ने गत दिनों जोशी को जमानत देने से इनकार कर दिया था और उसके बाद ईडी ने जोशी तथा उनके बेटे रोहित सहित, डेढ दर्जन आरोपियों के खिलाफ ईडी कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया था। इस दौरान, जोशी की पत्नी का निधन होने पर कोर्ट ने उन्हें दो बार अंतरिम जमानत का लाभ दिया था।

अमेरिका-चीन-पाकिस्तान गठबंधन भारत के लिए खतरनाक - खड़गे

खड़गे ने सवाल किया कि क्या प्रधानमंत्री भारत पर लगाये ट्रंप के बेबुनियाद आरोपों पर भी चुप रहेंगे

नयी दिल्ली, 31 जुलाई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के बयानों पर चुप्पी साधने वाले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को समझ लेना चाहिए कि भारत के खिलाफ अमेरिका पाकिस्तान तथा चीन का गठजोड़ बन रहा है और यह अत्यंत खतरनाक है।

खरगे ने कहा कि सैन्य कार्रवाई रोकने को लेकर ट्रंप के बयानों पर मोदी ने संसद में मौन व्रत धारण कर रखा था।

सवाल है कि अब ट्रंप ने भारत पर जो बेबुनियाद आरोप लगाए हैं, क्या उस पर भी प्रधानमंत्री चुप रहेंगे।

उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने आयात शुल्क की जो वजह बताई है कि वह चौंकाने वाली है। आयात शुल्क लगाने की वजह उन्होंने भारत द्वारा रूस से तेल आयात, भारत द्वारा रूस से हथियारों की खरीद, भारत का ब्रिक्स का सदस्य होना, ब्रिक्स का अमेरिकी डॉलर पर हमला बताया है। ये भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता वाली राष्ट्रीय नीति पर कड़ा प्रहार है।

खरगे ने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार में डॉ. मनमोहन सिंह ने अमेरिका सहित 45 देशों से परमाणु छूट दिलाई थी।

अमेरिका पाकिस्तान का तेल भंडार विकसित करेगा

नयी दिल्ली, 31 जुलाई। भारत और रूस के बीच दशकों पुराने सहयोग और मित्रता से बुरी तरह चिढ़े हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प ने भारत पर 25 प्रतिशत आयात शुल्क और जुर्माना लगाने के बाद अब पाकिस्तान के तेल भंडार के विकास में सहयोग के लिए उसके साथ एक नया समझौता किया है।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर बुधवार रात पाकिस्तान के तेल भंडार विकास समझौते की घोषणा की। उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान से एक नये व्यापार

- **ट्रंप ने कहा, मुझे परवाह नहीं है कि भारत-रूस के साथ क्या करता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दोनों मिल कर अपनी मृत अर्थव्यवस्थाओं को डुबा दें।**

ढ ांचे को अंतिम रूप दे दिया गया है। इसका मकसद पाकिस्तान के अप्रयुक्त तेल भंडार विकसित करना और आयात शुल्क घटाना है। इस काम के लिए अमेरिकी तेल कंपनी का चयन अभी नहीं हुआ है। यह कंपनी पाकिस्तान के 'विशाल तेल भंडार' के विकास का काम करेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने लिखा, हमने अभी-अभी पाकिस्तान के साथ एक समझौता किया है, जिसके तहत पाकिस्तान और अमेरिका अपने विशाल तेल भंडार को विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे।

क्या दिल्ली व वॉशिंगटन एक...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ऊर्जा और रक्षा संबंधों का गहराना और ब्रिक्स में उसकी मुखर भूमिका, इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिकी प्रभुत्व के लिए खतरा है। लेकिन भारत को टैरिफ से सज़ा देने की इस कोशिश में ट्रंप उस व्यापक रणनीतिक ढांचे की अनदेखी कर रहे हैं, जिसे बुश, ओबामा और बाइडन जैसे पूर्व राष्ट्रपतियों ने मिलकर तैयार किया था तथा जिसमें भारत को चीन के मुकाबले एक अहम संतुलन और लोकतांत्रिक साझेदार के रूप में देखा गया था।

रैंड कॉर्पोरेशन के डेरेक जे. ग्रॉसमैन ने 31 जुलाई 2025 को भारत-अमेरिका संबंधों का 1998 के बाद का सबसे बुरा दिन बताया। उनका कहना है कि लेन-देन आधारित, आवेगपूर्ण और सार्वजनिक रूप से टकराव करने वाली ट्रम्प की शैली ने इस पारंपरिक रूप से स्थिर रिश्ते को झकझोर दिया है। नवरूप सिंह ने ट्वीट किया कि 25 वर्षों की प्रगति पल भर में मिटा दी गई। यह बात, ट्वीट की गई कई अन्य विश्लेषकों की उस भावना को व्यक्त करती है, जिसमें ट्रंप की नाराज़गी के पीछे अमेरिका की विदेश नीति में भारत को लेकर सोच में बदलाव की आशंका नज़र आती है।

दक्षिण एशिया मामलों के विशेषज्ञ माइकल कुगेलमैन कहते हैं कि भारत ने ट्रंप के दूसरे कार्यकाल से मज़बूत रिश्ते की उम्मीद की थी, खासकर पहले कार्यकाल की दोस्ताना टोन के बाद। लेकिन शायद भारत ट्रंप की अनिश्चित विदेश नीति को लेकर सतर्क नहीं रहा। कृषि उत्पादों, डिजिटल टैक्स और दवाओं की कीमतों को लेकर भारत के अनमने रुख ने ट्रंप की उस लंबे समय से चली आ रही शिकायत को और हवा दी, कि व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में है, हालाँकि हाल के वर्षों में यह अंतर कम हुआ है।

यह टैरिफ एक दोतरफा ट्रेड वॉर को जन्म दे सकता है, जिसमें भारत भी जवाबी टैरिफ या रक्षा सौदों और महत्वपूर्ण खनिजों से जुड़े समझौतों को धीमा कर सकता है। लेकिन नुकसान केवल व्यापार तक सीमित नहीं रहेगा। दांव पर है भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी की पूरी संरचना, मालाबार जैसे संयुक्त नौसैनिक अभ्यासों से लेकर सेमीकंडक्टर, साइबर सुरक्षा और उन्नत तकनीक में सहयोग तक। ट्रंप द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था को मृत कहे जाने वाली टिप्पणी दिल्ली में कड़वाहट ही पैदा करेगी, जहाँ मोदी सरकार अमेरिका से निवेश आकर्षित करने और भारत को भरोसेमंद वैश्विक साझेदार दिखाने की कोशिश में लगी है।

इसके अलावा, यह कदम भारत को चीन और रूस के करीब ले जा सकता है, विशेषकर ब्रिक्स, एससीओ और ग्लोबल साउथ जैसे बहुपक्षीय मंचों में। वर्षों से भारत ने मॉस्को के साथ अपने पारंपरिक संबंधों और वाशिंगटन के साथ अपने बढ़ते सहयोग के बीच संतुलन बनाए रखा है। ट्रंप की यह कार्रवाई उस संतुलन को डगमगाने का जोखिम पैदा कर रही है।

अब, जबकि अगस्त के अंत में वार्ता का एक और दौर निर्धारित है, देखना यह होगा कि क्या कूटनीति इस रिश्ते को बचा सकती है। भारत ऐसी धमकियों के आगे झुकने वाला नहीं दिखता। नई दिल्ली एकतरफा समझौतों का लगातार विरोध करती रही है और 2026 के आम चुनावों को देखते हुए घरेलू राजनीतिक दबाव के चलते किसी भी प्रकार की ढील की संभावना कम है।

इस तरह, ट्रंप की टैरिफ नीति ने न केवल आर्थिक रिश्तों को खतरे में डाला है, बल्कि उस व्यापक रणनीतिक साझेदारी को भी संकट में डाल दिया है, जो 21वीं सदी की भू-राजनीति की नींव बन गई थी। अगर यह सिलसिला यूँ ही चलता रहा, तो दोनों देशों के दशकों के द्विदलीय (बाय पार्टिसन) प्रयास मिट्टी में मिल सकते हैं, जो आपसी सम्मान, रणनीतिक समन्वय और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित संबंध बनाने के लिए किए गए थे। अब सवाल केवल टैरिफ का नहीं है, बल्कि यह है कि क्या वाशिंगटन और नई दिल्ली समय रहते भरोसे को फिर से स्थापित कर सकते हैं?

राहुल 15 दिन की ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बातचीत करेंगे, जिन्हें मतदाता सूची से बाहर कर दिया गया है। विपक्षी नेता इस दौरान चुनाव आयोग और सत्तारूढ दल पर बड़ा हमला बोलेंगे। बिहार एसआईआर का मुद्दा संसद से लेकर बिहार की सड़कों तक गूंजता रहेगा, क्योंकि चुनाव आयोग जनता के जनादेश को छीनने का काम कर रहा है। बिहार में अगर मोदी एंड कम्पनी को हार का सामना करना पड़ा, तो यह उनकी राजनीति के लिए बड़ा झटका होगा।

मोदी पहले से ही कई मोर्चों पर मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, लेकिन, जैसा कि एक वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा, वे किसी भी कीमत पर बिहार की हार बर्दाश्त नहीं कर सकते।

जिस जूनून से अमेरिका ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ये सभी नई संधियाँ और समायोजन अमेरिका के राष्ट्रपति की उस हताशा से जन्मे हैं, जो उन्होंने खुद को वैश्विक मामलों का निर्णायक नेता स्थापित करने के प्रयास में दिखाई है। वे व्लादिमीर पुतिन के साथ अपने 'व्यक्तिगत करिश्मा' के ज़रिए यूक्रेन संकट सुलझाने की उम्मीद कर रहे थे, जिसमें वे पूरी तरह विफल रहे।

वे इज़रायल के नेता बेंजामिन नेतन्याहू के साथ भी कोई सफलता नहीं पा सके। गाज़ा में जारी मानवीय संकट को रोकने के उनके प्रयास बार-बार विफल रहे। नेतन्याहू ने गाज़ा और सीरिया पर हमलों में बार-बार अमेरिकी राष्ट्रपति की उपेक्षा की।

विदेश नीति में ट्रम्प की असफलता उनके पूर्ववर्ती की तरह ही सामने आई है, जिनकी उन्होंने तीव्र आलोचना की थी। अब वही कलंक खुद ट्रम्प पर चिपक गया है।

इस पृष्ठभूमि में, जब ट्रम्प की "डील मेकर" की छवि पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है, ट्रंप ने यूरोपीय संघ, जापान और ब्रिटेन के साथ व्यापार एजेंडे को आगे बढ़ाया। इसी तरह, उन्होंने भारत के साथ भी एकतरफा व्यापार समझौता करने की कोशिश की, लेकिन भारत ने झुकने से इनकार कर दिया।

भारत को सजा देने की ट्रम्प की उग्रता उनकी अधीरता को दर्शाती है। उन्होंने बार-बार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ अपनी 'दोस्ती' का दावा किया है, लेकिन अब वे भारत और मोदी दोनों को एक कठिन वार्ताकार मानते हैं, जिनसे वे निराश हैं।

ट्रंप ने भारत पर अधिक टैरिफ लगा दिए, जबकि व्यापार वार्ता अभी समाप्त नहीं हुई थी। अब वे रूसी कच्चे तेल की भारतीय खरीद पर और अधिक टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं, जो अभी घोषित नहीं हुए हैं। खास बात यह है कि उन्होंने चीन पर ऐसा कोई टैरिफ नहीं लगाया है, जबकि वह भी रूस से भारी मात्रा में तेल खरीद रहा है।

इससे भारत एक दोहरे संकट में फंस गया है। अमेरिका और भारत के बीच सहयोग की अपेक्षा थी, लेकिन अब वे विरोधी पक्षों में खड़े दिख रहे हैं।

इस बीच, असली लाभार्थी चीन बन रहा है। अंतरराष्ट्रीय मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार, चीन पहले से ही अमेरिका के साथ एक समझौते पर बातचीत कर रहा है और यह वार्ता स्टॉकहोम में प्रगति पर है। अगर यह सौदा हो जाता है, तो अमेरिका अपनी निगाहें भारत जैसे अन्य देशों पर केन्द्रित कर सकता है।

विपक्ष ने दिन ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

के बाद, शून्यकाल शुरु करते हुए सदन की कार्यवाही प्रारंभ की, लेकिन विपक्षी दलों के सदस्य हंगामा और नारेबाजी करते हुए सदन के बीचोंबीच आ गये। हंगामा बढ़ ने लगा तो बिरला ने सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी।